



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

12/3/86

सं० 616]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 1986/पाउस 3, 1908

No. 616]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 1986/PAUSA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जन-सुनल परिवहन मंत्रालय

अनुसूची

(पलन पक्ष)

मरगाव पलन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) (प्रथम मशोखन) विनियम,  
1986

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1314 (अ) —केंद्रीय सरकार, महा पलन न्याम अधि-  
नियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 132 की उपधारा (1)  
के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करने हुए एतद्वारा जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची  
में उल्लिखित है, मरगाव पलन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) (प्रथम  
मशोखन) विनियम, 1986 को अनुसूचित करती है।

2 ये विनियम इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने  
की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. पी.आर.-12016/8/86-पी.ई. 1]  
पी.एम. अकहम, अपर सचिव

प्रमुख पलन अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 124  
(1) और (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करने हुए मरगाव पलन न्याम का न्यासी मण्डल इसके द्वारा मरगाव  
पलन न्याम कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1964 को पुनः  
मशोखित करने के लिए अधोलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

1 (1) ये विनियम, मरगाव पलन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत)  
(प्रथम मशोखन) विनियम, 1986 को कहें जायेंगे।

2. मरगाव पलन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1984  
इसके अर्थों इसे नव विनियम कहा गया है के उप-विनियम (1) के  
निम्नलिखित शब्दों को छोड़ दिया जाए यथा—

(1) "ऐसा कर्मचारी जिसका गृह निवास स्थान 400 कि.मी. के  
भीतर स्थित है सहित-प्रथम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 180  
कि.मी."

(2) प्रथम 400/160 कि.मी. के बाधन बिना किसी कटौती के दानो और की संपूर्ण दूरी के लिए किराये की प्रतिपूर्ति की जाए को छोड़कर”

(3) “तथापि, गृह निवास स्थान के लिए छूटी यात्रा रियायत के बारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके तहत कर्मचारी को प्रथम 400/160 की भी स्थिति हो, को दूरी के किराये का वास्तविक लेना होगा।”

3. मूल विनियम के विनियम 5 में—

(क) वर्तमान उप-विनियम (1) को छोड़ दें और निम्नलिखित उप-विनियम (1) को जोड़ दिया जाए, यथा :—

“प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का हर एक कर्मचारी इस रियायत की पाले के लिए हकदार है। प्रत्येक मामले में यात्रा “गृह निवास स्थान” और वापसी का होना चाहिए तथा दावा यात्रा प्रारंभ करने तथा वापसी के लिए होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यात्रा का प्रारंभ और वापसी मुख्यालय में ही हो। किन्तु वास्तविक यात्रा की दूरी के लिए राहत रकम के लिए ही सहायता दी जाएगी और यह रकम कर्मचारी द्वारा मुख्यालय में गृह निवास स्थान और वापसी की यात्रा करने पर राहत रकम के लिए ही सहायता दी जाएगी और यह रकम कर्मचारी द्वारा मुख्यालय में गृह निवास स्थान और वापसी की यात्रा करने पर राहत रकम तक ही सीमित रहेगी।

(ख) वर्तमान उप-विनियम (2) को छोड़ दिया जाये और निम्नलिखित उप-विनियम (2) को रखा जाए, यथा :—

“(2) कर्मचारी किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकता है, किन्तु मण्डल की सहायता हकदार श्रेणी अथवा निचली श्रेणी, जो भी स्थिति हो, में वास्तविक उपयोग तक ही सीमित रहेगी।”

4. मूल विनियम के विनियम 10 में—

(क) उप विनियम (1) में “400 कि.मी. (160 कि.मी. चतुर्थ श्रेणी के मामले में) से अधिक दूरी के लिए” शब्दों को छोड़ दिया जाए।

(ख) उप विनियम (2) के पञ्च भाग में प्रारंभ होने वाले “इस प्रकार के मामले में” और अंत होने वाले “तब शेष रहेगा” शब्दों को छोड़ दिया जाए और इसके स्थान पर अधोनिखित को रखा जाए—

“इस प्रकार के मामले में, मण्डल की सहायता, मुख्यालय और गृह निवास स्थान के बीच की दूरी अथवा प्रेषित दर्शनीय स्थान (भारत में किसी भी दर्शनीय स्थान जाने की योजना के तहत दावे के मामले में को छोड़े गये) से किए गए त्रयवार/निचली श्रेणी के वास्तविक उपयोग के लिए किराये, जो भी कम है, तक ही सीमित होगी।”

(ग) उप-विनियम (3) को छोड़ दिया जाए और इसके स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, यथा :—

“(3) ग्राम तौर पर उच्च श्रेणी में यात्रा करने के लिए हकदार कर्मचारी इस रियायत का लाभ उठाने समय डीवकम बानानूकूल रेल मार्गों के निचली श्रेणी में सफर कर सकता है। इस प्रकार के मामले में निचली श्रेणी के किराये पर लगाने वाले अधिभार की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा की जाएगी।”

(घ) उप-विनियम (4) में “ग्राम तौर पर यात्रा करने के लिए हकदार” और “रेलवे प्रवासा” शब्दों के बीच आने वाले “प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी” तथा “यात्रा कर सकते हैं” और “स्वी-पर आवास का उपयोग कर सकते हैं” के बीच आने वाले “तृतीय श्रेणी” शब्दों को छोड़ दिया जाए और इसके स्थान पर क्रमशः “उच्च श्रेणी” और “निचली श्रेणी” शब्दों को रखा जाए।

(च) उप-विनियम (6) में—

“उदाहरण के लिए 400 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 160 कि.मी.) के लिये” को छोड़ दिया जाए।

(ङ) उप-विनियम (7) के पञ्च भाग में “जहाँ इस प्रकार की यात्रा प्राइवेट कार से की गई है” से प्रारंभ और “अथवा अथवा उपाध्यक्ष के सम्मोचन के अधीन” से अंत शब्दों को छोड़ दिया जाए और इसके स्थान पर अधोनिखित को रखा जाए—

“कार्टेज बस, रैन अथवा अन्य वाहनों से की गई यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी, यदि इसके मालिक प्राइवेट कार्टेज है। तथापि, सरकारी पब्लिक बिक्रम निगम, राज्य सरकार पब्लिक और अन्य सरकारी अथवा स्थायी विकास द्वारा संचालित कार्टेज बस, रैन अथवा अन्य वाहनों में यात्रा करने पर कोई रोक नहीं है।”

(ज) उप विनियम (8) में, “परन्तु यह कि प्रथम 400 अथवा 160 कि.मी. जैसी भी स्थिति हो, के भीतर सुपर फास्ट रेल में की गई संपूर्ण यात्रा प्रानी है तो इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी” शब्दों को छोड़ दिया जाए।

5. मूल विनियम के विनियम-II के उप-विनियम (2) के साथ एक नया उप-विनियम (3) जोड़ दिया जाए, यथा :—

“3. कार्टेज बस, रैन अथवा अन्य वाहनों में की गई यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, यदि इसके मालिक प्राइवेट कार्टेज है। तथापि, सरकारी पब्लिक बिक्रम निगम, राज्य सरकार पब्लिक और अन्य सरकारी अथवा स्थायी विकास द्वारा संचालित कार्टेज बस, रैन, अथवा अन्य वाहनों में यात्रा करने पर रोक नहीं है।”

6. वर्तमान मूल विनियम के विनियम 11 को छोड़ दिया जाए और वर्तमान विनियम 15 से 27 की संख्या को प्रथम 11 से 26 तक की संख्या सख्या दी जाए।

7. (1) विनियम 16 (अब जिसकी संख्या 15 है) के उप-विनियम (1) के समापन भाग में आने वाले “800 कि.मी. (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 320 कि.मी.) सहित” शब्दों को छोड़ दिया जाए।

(2) इसी प्रकार विनियम 16 (अब जिसकी संख्या 15 है) के उप-विनियम के नीचे “उदाहरण” शब्द को छोड़ दिया जाए।

8. मूल विनियम के विनियम-21 (जो तारीख संख्या 20 है) में :—

(1) प्रारंभिक भाग में प्रत्येक कर्मचारी “ज प्रारंभ और “जैसी भी स्थिति हो” से अंत तथा

(2) “की नकद प्रतिपूर्ति” और “कंपाउंड बी” शब्दों के बीच आने वाले “बोकी” शब्द को छोड़ दिया जाए।

वि.सू. सामान्य कानूनी नियम की सख्या और मूल विनियम तथा इसके बाद के संशोधनों को प्रकाशित करने की तारीख :

1. मूल नियम ना.का.नि सं 959 दिनांक 22-6-64 भारतीय विशेष राजपत्र भाग-II, अनुभाग 3. उप-अनुभाग (i) विलास 1-2-64 में प्रकाशित।

2. बाद के संशोधन :

(1) केंद्रीय सरकार का संज्ञा सं. 7-पी ई. (26)/73 दिनांक 30-6-73 गोवा, दमन और दीव सरकार के सरकारी राजपत्र के सीरीज III सं. 16 दि. 19-7-73 में प्रकाशित।

2. केन्द्रीय सरकार की मंजूरी सं. पी. ई. जी. (9)/75 दिनांक 2-4-75 मोबा, दमन और दीव सरकार के सरकारी राजपत्र के सीरीज-III, सं. 4 दिनांक 25-4-75 में प्रकाशित।

3. केन्द्रीय सरकार की मंजूरी सं. पी. ई. जी. (20)/75 दिनांक 18-8-75 मोबा, दमन और दीव सरकार के सरकारी राजपत्र के सीरीज-III, सं. 13 दिनांक 4-9-75 में प्रकाशित।

4. केन्द्रीय सरकार की मंजूरी सं. पी. ई. जी. (4)/79 दिनांक 19-9-79 मोबा, दमन व दीव सरकार के सरकारी राजपत्र के सीरीज-III, सं. 11 दिनांक 14-6-79 में प्रकाशित।

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 24th December, 1986

### NOTIFICATION

GSR 1314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the 'Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) (First Amendment) Regulations, 1986 made by the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[FW PR-12016/8/86-PE.I]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

### SCHEDULE

#### MORMUGAO PORT EMPLOYEES' (LEAVE TRAVEL CONCESSION) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 1986

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) and (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Mormugao Port Trust, hereby makes the following regulations further to amend the 'Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1964 namely:

1. (i) These regulations may be called the 'Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) (First Amendment) Regulations, 1986.

2. In Regulation 4 of the 'Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the principal Regulations):

In Sub-Regulations (1) the words:

(i) "including those whose home towns are situated within 400 kms. or in case of Class IV employees 160 kms."

(ii) "except that the reimbursement of fare may be allowed for the entire distance both ways without any deduction in respect of the first 400-160 kms."

(iii) "There will, however, be no change in regard to the Leave Travel Concession to home town under which an employee will have to bear the liability in respect of the first 400/160 kms. as the case may be." shall be deleted.

3. In Regulation 5 of the principal Regulations:

(a) Delete the existing sub-regulation (1) and substitute the following sub-regulation (1) namely:—

"(1) Every employee of the I, II, III and IV grades shall be entitled to the concession. In every case the journey should be to the "home town" and back and the claim should be for both outward and return journeys. The journey need not necessarily commence from or end at the headquarters of an employee either in his own case or in the case of his family. But the assistance admissible shall be the amount admissible for the actual distance travelled, limited to the amount that would have been admissible had the journey been performed between the headquarters and the home town of the employee".

(b) Delete the existing sub-regulation (2) and substitute the following sub-regulation (2) namely:—

"(2) An employee may travel in any class, but the Board's assistance shall be limited to the fares for accommodation by the entitled class or the lower class, as the case may be to the extent actually used."

4. In Regulation 10 of the principal Regulations:—

(a) in sub-regulation (1) the words "for the distance in excess of 400 kms. (160 kms. in the case of the fourth grade)" shall be deleted the later portion of sub-regulation (2), beginning with the words "in such a case" and ending with the words "will then be the balance" shall be deleted and instead the following shall be substituted:—

"In such a case, the Board's assistance shall be the fare for the entitled/lower class actually used, by the shortest route between the headquarters and the Home Town or the declared place of visit (in case of claim under the scheme to visit "any place in India)" whichever is less".

(c) Sub-regulation (3) may be deleted and instead the following shall be substituted:—

"(3) An employee who is normally entitled to travel by higher class may travel in lower class in the deluxe air-conditioned trains while availing himself of the concession. The cost on account of the surcharge over the lower class fare which is levied in such a case shall also be reimbursed by the Board".

(d) In Sub-regulation (4), the words "I or II class" appearing between the words "normally entitled to travel by" and "of railway accommodation" and the words "III class" appearing between the words "may travel by" and "and avail of the 'sleeper' accommodation" shall be deleted and substituted by the words "higher class" and "lower class" respectively.

(e) In Sub-regulation (6) the words:—

"beyond the first 400 kms. (160 kms. in the case of employees of the fourth grade) for example." shall be deleted.

(f) the later portion of Sub-regulation (7) beginning with the words "where such journey is performed by private car" and ending with the words "subject to the approval of the Chairman or the Deputy Chairman" shall be deleted and instead the following shall be substituted:—

"The reimbursement of the fare for journeys undertaken in a chartered bus, van or other vehicles

shall not be admissible in so far such vehicles are owned by private operators. There is, however, no bar to travel by buses, vans or other vehicles, on charter where these vehicles are operated by Tourism Development Corporations in the Public Sector State Transport Corporations and Transport Services run by other Government or Local Bodies."

- (g) in Sub-Regulation (8) the words "provided that no reimbursement will be allowed where the entire journey by Super Fast Express train falls within first 400 or 160 kilometres as the case may be." shall be deleted.

5. In Regulation 11 of the principal Regulations, after Sub Regulation (2), insert a new Sub-Regulation (3), namely:—

- "(3) The fare for journey undertaken in a chartered bus, van or other vehicles owned by private operators is not reimbursable. However, there is no bar, to travel by buses vans or other vehicles on charter where these vehicles are operated by Tourism Development Corporation in the public sector State Transport Corporation and transport services run by other Government or Local Bodies."

6. The existing Regulation 14 of the principal Regulations shall be deleted and the existing Regulations 15 to 27 shall be renumbered as 14 to 26 respectively

7. (1) The words "plus 800 kilometres (320 kilometres in the case of employees for fourth grade)", appearing at the concluding portion of sub-Regulation (1) of Regulation 16 (now renumbered as 15) shall be deleted.

(2) Similarly "Illustration" below Sub-Regulation (1) of Regulation 16 (now renumbered as 15) shall be deleted.

8. In Regulation 21 (now renumbered as 20) of the principal Regulations:—

- (i) The initial portion beginning with the words "Every employee" and ending with the words "as the case may be", and
- (ii) the word "remaining" appearing between the words "Cash, reimbursement of the" and "fare shall be" shall be deleted.

N.B. GSR No. and date of publication of the principal Regulations and the subsequent amendments:

1. Principal Regulation: GSR No. 959 dated 22-6-64 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sec. 3, Sub-Sec (i) dated 1-7-64.

2. Subsequent Amendments:

- (i) Central Government's sanction No. 7-PE(26)/73 dated 30-6-73, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu Series III, No. 16 dated 19-7-73.
- (ii) Central Government sanction No. PEG(9)75 dated 2-4-75, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 4 dated 25-4-75.
- (iii) Central Government's sanction No. PEG(26)/75 dated 18-8-75, published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 23 dated 4-9-1975.
- (iv) Central Government sanction No. PEG (4)/79 dated 19-5-79 published in the Official Gazette of Government of Goa, Daman and Diu, Series III, No. 11 dated 14-6-79.